विचार बिन्दु

अज्ञान जैसा शत्रु दूसरा नहीं। –चाणक्य

विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन सरकार कहां है?

पहलगाम की जघन्य आतंक वादी घटना के बाद देश के सभी विपक्षी दलों ने लगातार यह बयान दिए हैं कि वे हत्यारे आतंकवादियों और पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं। विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी ने, प्रेस कांफ्रेंस के जरिए यह बात दोहराई है कि देश, सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रकार की एकता राजनीतिक दलों के मध्य बहुत कम ही दिखाई देती है ।

एक ओर जहां विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा है, वहीं आश्चर्य की बात है कि सरकार ने इस घटना के 12 दिन बाद भी आतंकवादियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। केवल प्रधानमंत्री के बयान ही आए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि वे आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को पृथ्वी के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। यदि बयानों के आधार पर आतंकवाद समाप्त हो जाता, तो अब तक शायद कभी का हो चुका होता।

भारत ने सिंधु जल समझौते को एक तरफा स्थगित करके पाकिस्तान पर दबाव बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उसका भी धरातल प्रभाव कुछ वर्षों बाद ही दिखाई देगा। दोनों ही देशों ने अपने उच्चायोगों में स्टाफ को आधा कर दिया। दोनों ने अपने-अपने हवाई क्षेत्र में एक दूसरे की वायु उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में एक निश्चित समय सीमा में भारत छोड़ने और पाकिस्तान जाने के आदेश दे दिए हैं। पाकिस्तान ने भी इसी प्रकार भारतीयों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कह दिया है। इन सब कदमों से जनता संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। जनता चाहती है कि आतंकवादियों को पकड़ कर उनके नेटवर्क को नेस्तनाबूत किया जाए।

इस प्रकार की घटना होने के संबंध में कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और विपक्षी दलों द्वारा सुरक्षा में चूक का प्रश्न उठाया गया एवं जांच की बात की गई, तो यह सरकार को पसंद नहीं आया। हद तो तब हो गई, जब कई प्रमुख सोशल मीडिया चैनलों को सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके प्रतिबंधित कर दिया। इससे पूर्व उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया। इनमें 4 पीएम चैनल प्रमुख है जिसे लाखों लोग देखते हैं। जब लोकगायिका नेहा सिंह राठौड़ ने सरकार द्वारा सुरक्षा में चूक होने की बात कही और घटना स्थल पर किसी भी प्रकार के सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति पर प्रश्न उठाए तो उत्तर प्रदेश में उन पर एफ आई आर दर्ज करा दी गई। सरकार को ऐसा लगने लगा कि सुरक्षा में कमियों की बात उठाकर लोगों ने देशद्रोह किया है। वास्तव में देशद्रोह तो वह है जिसके चलते, सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई बरती गई और जहां 2000 पर्यटक जाते हों ,वहां कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो । कहा गया है 'समरथ को नहीं दोष गोसाईं'। राष्ट्रीय मीडिया पर तो सरकार का एक प्रकार से एकाधिकार है । वही खबरें चलाई जाती हैं जो सरकार का गुणगान करें। सोशल मीडिया के कुछ साहसी पत्रकार अवश्य बार-बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं किंतु कहीं से उत्तर नहीं मिल रहा है।

सामान्यतया, प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी घटना पर देश को संबोधित कर देते हैं, किंतु कई गत कई वर्षों की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने नागरिकों को अभी तक संबोधित नहीं किया है। जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर आए थे तो लगा था कि वे कश्मीर जाएंगे तथा उन परिवारों से भी मिलेंगे जिनके परिजनों ने इस आतंकवादी घटना में अपने प्राण गंवाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ । इस दर्दनाक घटना के दो दिन बाद ही, प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित करने बिहार पहुंच गए। उस रैली में नीतीश कुमार के साथ हंसी मजाक करते हुए उनका वीडियो खूब वायरल हुआ। उस समय तक तो शहीदों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। यह दृश्य, मृत पर्यटकों के परिजनों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा ही था।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने मुम्बई में 'वेव्स' (world Audio Visual and Entertainment Summit) नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में कई घंटे बिताए, जिसमें देश और विदेश की कई फिल्मी हस्तियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री से, जब देश यह अपेक्षा कर रहा था कि पहलगाम की घटना की गंभीरता को देखते हुए उनकी ओर से कोई वक्तव्य आएगा, वहीं मनोरंजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का इतने लंबे समय तक उपस्थित रहना देशवासियों को अच्छा नहीं लगा । क्या प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन हो गए हैं?

बात केवल यहीं पर नहीं रुकी। सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री जी गौतम अडानी के साथ केरल में आयोजित एक समारोह में देखे गए, जहां अडानी के बंदरगाह का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। वहां भी वह विपक्ष पर कटाक्ष करना नहीं भूले और यहां तक कह दिया कि इस कार्यक्रम में शशि थरूर आने से विपक्षियों की नींद उड़ गई होगी। प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की हल्की भाषा का उपयोग कतई उपयुक्त नहीं है, विशेष कर ऐसे संवेदनशील समय में, जब पूरे देश में पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भयंकर आक्रोश है ।

आश्चर्य का विषय तो यह भी है की सारी तकनीकी प्रगति के बावजूद, अभी तक सरकार चार आतंकी जो इस घटना में सम्मिलित थे, का कोई पता नहीं लगा पाई है। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट, जांच एजेंसी एन आई ए को प्राप्त हो गए हैं जिसके आधार पर उन्हें ढूंढ निकालना आसान होगा। घटना के 12 दिन बाद भी, अभी तक चारों आतंकवादी सरकार की पहुंच से बाहर हैं । क्या यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी भूल गए कि कैसे वे प्रत्येक आतंकवादी घटना के बाद तत्कालीन सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर शक प्रकट करते हुए तंज़ कसते थे? आज का विपक्ष कम से कम, सरकार के साथ पूरी तरह खड़ा तो है। जब विपक्ष अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है तो सरकार क्यों जिम्मेदारी से भाग रही है और देश का ध्यान भटकाने का काम कर रही है?

अब भी, सरकार को अविलंब देशवासियों के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह घटना क्यों हुई और अब तक आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए हैं? पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई में क्या अमेरिका का दबाव काम कर रहा है? अमरिकी दबाव को मानने का कारण कहीं गौतम अडानी के विरुद्ध अमेरिका में चल रहे न्यायिक कार्रवाई में वहां की सरकार से सहायता प्राप्त करना तो नहीं है?

सरकार द्वारा अब तक पाकिस्तान के आतंकियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं किए जाने के पीछे, कहीं अमेरिका का दबाव तो नहीं है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपना व्यक्तिगत मित्र बताते हैं, ने तो यहां तक कह दिया कि भारत और पाकिस्तान को मिल बैठकर शांति के प्रयास करना चाहिए ताकि सीमा पर किसी प्रकार का तनाव न बढ़े। क्या प्रधानमंत्री जी देश के आक्रोश की परवाह किए बिना अमेरिका द्वारा दी गई सलाह को मान रहे हैं? पाठकों को यह पता होगा कि एक बार पहले भी अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कही थी। उल्लेखनीय है कि भारत ने कभी इस प्रकार के प्रयासों को स्वीकार नहीं किया और सदैव सिरे से खारिज कर दिया है ।

आश्चर्य की बात तो यह है कि जो मीडिया चैनल सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, वह उन्हीं पर प्रतिबंध लगा रही है। वह उन व्यक्तियों पर भी एफआईआर दर्ज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, जो सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं और जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। क्या नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि आतंकवादी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए एवं यह घटना किस प्रकार संभव हो पाई? क्या गृहमंत्री अमित शाह ने बार-बार यह आश्वासन नहीं दिया था कि कश्मीर में सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है और वहां पर स्थिति सामान्य है? इसी विश्वास के सहारे पर्यटक इतनी बड़ी संख्या में कश्मीर जाने लगे थे । उन्हीं में से 26 लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी ।

सत्ताधारी दल के कई नेता, विपक्षी दलों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार से सुरक्षा में चूक के बारे में प्रश्न पूछ कर वे, एक प्रकार से पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं। यह विचित्र बात है, क्योंकि अपनी सरकार से प्रश्न पूछना, किसी भी शत्रु देश की सहायता करना किस प्रकार हो सकता है? मारे गए व्यक्तियों के परिवार भी बार-बार यह कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई? यदि वहां पर सुरक्षा बल होता तो उनकी जान बच जाती ।

जब देश, प्रधानमंत्री से पहलगाम की घटना के बदले की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी अचानक एक सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा कर दी कि केंद्र सरकार आगामी जनगणना के साथ ही जातिगत जन गणना भी करवाएगी। न केवल यह, उन्होंने इसका पूरा श्रेय सत्ताधारी दल को देते हुए इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। इसी प्रकार की बात सत्ताधारी दल के अन्य सभी नेता भी करने लगे हैं। जो लोग अब तक जातिगत गणना की मांग करने वालों को पानी पी-पी कर कोस कर रहे थे, वे ही अब जातिगत गणना के निर्णय की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। पाठकों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि गत कई वर्षों से जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात पुरजोर ढंग से संसद एवं बाहर उठा रहे थे, भाजपा के नेता इसका घोर विरोध करते रहे थे । प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक पॉडकास्ट में जाति गत जनगणना की मांग करने वालों को 'अर्बन नक्सल' तक कह दिया था। भाजपा के प्रमुख नेता नितिन गडकरी ने तो एक सार्वजनिक भाषण में यहां तक कह दिया "जो करेगा जाति की बात, उसे मारूंगा कस कर लात"। ऐसी पृष्ठभूमि में अचानक जाति गत जनगणना का निर्णय लेना सबको आश्चर्यचकित करने वाला है । ऐसा लगता है कि इस निर्णय से, पहलगाम की घटना से, देश का ध्यान भटकाने का प्रयास तो नहीं किया गया है ?

हम इस लेख में जातिगत जनगणना के गुणवगुण पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह कहना चाह रहे है कि जाति गत जनगणना की बात करने वालों को अर्बन नक्सल की संज्ञा देने वाले अचानक जातिगत जनगणना की बात क्यों करने लगे? हमारे नेता शायद यह मानकर चलते हैं कि यहां के देशवासियों की याददाश्त बहुत कमजोर है और उन्हें कुछ नहीं पता कि कुछ दिन पहले वे इसी विषय पर क्या कह रहे थे? हां, यह अवश्य है कि इसका राजनीतिक लाभ बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा लेने का प्रयास करेगी।

अब भी, सरकार को अविलंब देशवासियों के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह घटना क्यों हुई और अब तक आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए हैं? पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई में क्या अमेरिका का दबाव काम कर रहा है? अमरिकी दबाव को मानने का कारण कहीं गौतम अडानी के विरुद्ध अमेरिका में चल रहे न्यायिक कार्रवाई में वहां की सरकार से सहायता प्राप्त करना तो नहीं है?

यह कभी कभार ही होता है, जब पूरा विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा हो, किंतु सरकार अपने कर्तव्य से विमुख होती हुई दिखाई दे ।

समय रहते सरकार को, विशेष कर प्रधानमंत्री जी को अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए यह सिद्ध करना चाहिए कि वे किसी विदेशी दबाव के आगे झुकने वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो?

फिलहाल तो देश वासी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, "विपक्ष तो सरकार के साथ है, पर सरकार कहां है?"

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

"कार्ल मार्क्स और वर्तमान दुनिया"

कार्ल मार्क्स जयंती के अवसर पर....

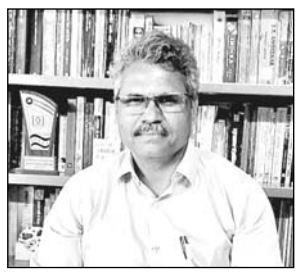

डॉ. रमेश बैरवा

5 मई को विश्वविख्यात क्रांतिकारी चिंतक कार्ल मार्क्स का जन्मदिन मनाया गया। ऐसे मार्क्स जिन्हें बीबीसी ने सहस्त्राब्दी का सबसे प्रभावशाली दार्शनिक माना है। जिन्होंने साम्यवाद का आदर्श दुनिया के सामने रखा। ऐसा साम्यवाद जिसमें निजी संपति के पूर्ण उन्मूलन के साथ समाज वर्गविहीन, राज्यविहीन हो जाता है। जहां विषमता, भेदभाव, बेरोजगारी, जाति, जेंडर, धर्म, रंग-रूप, भाषा, राष्ट्र के आधार पर लोगों में वैमनस्य नहीं रहता। हर प्रकार के शोषण,अन्याय से समाज मुक्त हो जाता है। मजदूर, मेहनतकशों के शोषण और प्राकृतिक संसाधनों के बेरहमी से दोहन पर आधारित मुनाफे से संचालित पूंजीवादी समाज के स्थान पर साम्यवादी समाज की स्थापना होगी जो "एक ऐसा संघ होगा, जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की शर्त होगी।"

ऐसे कार्ल मार्क्स का जन्मदिवस है जिन्होंने सबसे पहले मानव समाज के विकास के नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या की। द्वंदात्मक भौतिकवाद का दर्शन दिया जिसके आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक है कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में अंतर्निहित मानव शोषण एवं व्यवस्था के संकट के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण दिया। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। पूंजीवादी समाज में अंतर्निहित मानव अलगाव के बारे में बताया। पूंजीवाद के साम्राज्यवादी स्वरूप के बारे में भी बताया। मार्क्स ने यह भी बताया कि पूंजीवादी आर्थिक शोषण को कायम रखने एवं इसको बढ़ाने के लिए कैसे सामाजिक भेदभाव का उपयोग किया जाता है। कैसे महिलाओं का शोषण बरकरार रखा जाता है। कैसे जाति, रंगभेद, राष्ट्रवाद का इस्तेमाल मेहनतकश तबके के आर्थिक शोषण को कायम रखने के लिए किया जाता है।

कार्ल मार्क्स का जन्म प्रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में 5 मई, 1818 को हुआ था। मार्क्स के पिता एक वकील थे एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिमनेजियम में पूरी हुई। बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात् बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया। जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से भी बहुत प्रभावित थे। जर्मनी में जन्में लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण अपनी मृत्यु तक निर्वासित, तकलीफों का जीवन जीने वाले ऐसे महान अर्थशास्त्री मार्क्स का जन्मदिन है, जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की कार्यप्रणाली के सबसे बेहतरीन तथ्यपरक, वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए विश्व प्रसिद्ध पुस्तक 'दास कैपिटल' की रचना की थी। मार्क्स ने अपने विश्लेषण में बहुत सटीक तरीके से समझाया है कि समाज में असमानता व्यक्ति के लालच के कारण नहीं जैसा कि अनेक आदर्शवादी, धार्मिक विद्वान मानते हैं, बल्कि स्वयं इस पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया-अतिरिक्त मूल्य में ही निहित है। पूंजीवाद मूलत: शोषण और अन्याय पर आधारित व्यवस्था है जिसे उखाड़ फेंकने के लिए इसने अपने विरोधी सर्वहारा वर्ग को पैदा कर लिया है। मार्क्स ने लिखा है कि "मजदूर वर्ग द्वारा क्रांति में पहला कदम लोकतंत्र की लड़ाई जीतने के लिए सर्वहारा वर्ग को शासक वर्ग के पद पर उठाना है।" ऐसे कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है आज जिनका मानना था कि "कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सकता यदि वह दूसरे राष्ट्रों का शोषण करता है।" मार्क्स ने पूंजीवाद की वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में 1848 की रचना 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' में ही बता दी थी।

मार्क्स लिंग समानता के प्रबल पक्षधर थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी भी जानकारी रखता है, वह यह जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं का उत्थान किये असंभव है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखकर किसी समाज की सामाजिक प्रगति मापी जा सकती है। 1848 में ही मार्क्स के विचार इतने दूरदर्शी थे,वे चाहते थे कि "सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा। वर्तमान स्वरूप में बच्चों के कारखाने में काम करने का उन्मूलन। शिक्षा का औद्योगिक उत्पादन के साथ संयोजन" किया जाए। देश भर में जनसंख्या के अधिक समतापूर्ण वितरण द्वारा शहर और गांव के बीच के सभी भेदों को धीरे-धीरे समाप्त हो।

वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, संस्थापक, मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले मार्क्स को दुनिया आज भी याद करती है। जब कई पूंजीवादी विद्वान तो 'इतिहास का अंत' बताकर समाजवाद पर पूंजीवाद की अंतिम विजय की घोषणा कर चुके हैं। मार्क्सवाद की मृत्यु की घोषणा कर चुके हैं ! लेकिन स्मरण रहे जब तक दुनिया में शोषण है, अन्याय है, विषमता, भेदभाव, बेरोजगारी है तब तक कार्ल मार्क्स प्रासंगिक रहेंगे। तेजी से बढ़ती आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, प्राकृतिक संसाधनों के बेरहमी से दोहन के मौजूदा दौर में तो मार्क्स और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। मार्क्स की मूल रचनाओं का अध्ययन विद्यार्थियों को जरूर करना चाहिए।

–डॉ. रमेश बैरवा,
राज. विज्ञान के प्रोफेसर हैं।

शादियों में फीकी पड़ने लगी बैंड-बाजे की गूंज

- **बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर बैंड व्यवसायी**
- **डीजे के बढ़ते चलन से बंद होने की कगार पर पहुंचे बैंड-बाजे**

डीडवाना, (निसं)। शादी-विवाह का नाम आते ही जेहन में शहनाई की गूंज और बैंड की मधुर धुन का ही ख्याल आता है। शादी जैसे खुशी की रौनक बैंड-बाजा ही बढ़ाता है। कुछ सालों पहले तक हर बारात में बैंड की धुनें ही गूंजती थी। धार्मिक आयोजनों और उत्सवों में भी बैंड-बाजों का विशेष महत्व था, मगर बदलते दौर में बैंड-बाजों की धुन अब गुमनामी के अंधेरे में खोती जा रही है।

बदलते दौर में बैंड व्यवसायी काम नहीं मिलने से बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं।

बैंड वादक सिराज और गुलाम रसूल बताते हैं कि आधुनिक डीजे के चलन में आने के बाद बैंड का चलन अब कम होने लगा है। जिसका सीधा असर बैंड व्यवसाय से जुड़े लोगों और उनके परिवारों पर पड़ने लगा है और वे बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। एक समय था जब शादी के मौके पर बैंड बाजे की बुकिंग के लिए महीनों पहले से लाइन लगानी पड़ती थी। बैंड वालों के पास इतना काम होता था कि उन्हें दिनभर में कई कई शिफ्टों में काम करना पड़ता था। शादी-विवाह के अनेक उत्सव में एक उत्सव बारात में बैंड भी होता था। जब कही बैंड की आवाज आती थी तो सहज ही लोग यह अनुमान लगाते थे कि आसपास शादी समारोह का आयोजन चल रहा है। बैंड में गूंजती शहनाई की मधुर आवाज और बैंड का शालीन संगीत मन को सुकून देता था।

बैंड पर बाराती अपने आप झूमने नाचने लगते थे। कुछ सालों पहले तक हर शादी में बैंड की धुनें ही गूंजती थी। बैंड भारतीय संस्कृति और कला की जीवंत झांकी दर्शाते थे। मगर यह बैंड बाजा आधुनिक भारत में न केवल लुप्त होता जा रहा, बल्कि इससे जुड़े एक पूरे वर्ग पर रोजी रोटी का भी संकट आ खड़ा हुआ है। अब इन शादियों में शहनाई की गूंज की बजाय डीजे का तेज आवाज वाला संगीत बजने लगा है। बदलते दौर में बैंड-बाजों की धुन अब गुमनामी के अंधेरे में खोती जा रही है और आधुनिक डीजे के चलन में आने के बाद अब बैंड-बाजा संचालकों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे इस परंपरा और रोजगार दोनों पर संकट उत्पन्न होने लगा है। बदलते वक्त के साथ शादियों में बैंड बाजे की गूंज अब कम सुनाई देने लगी है।

अब बैंड के स्थान पर डीजे का चलन तेजी से बढ़ने लगा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अबूझ सावे के खास अवसर पर भी बैंड बाजों का काम ठप है। जिन बैंड वादकों को बाजा बजाने से फुर्सत नहीं मिलती थी, वो आज एकाध बुकिंग को भी तरसने लगे हैं। काम की कमी से बैंड व्यवसाय से जुड़े दर्जनों परिवारों पर इसका सीधा असर होने लगा है।

कभी 11 से लेकर 31 लोगों तक को रोजगार देने वाले इस कार्य से जुड़े लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इसके चलते इस परंपरागत व्यवसाय का धीरे-धीरे दम टूट रहा है। काम नहीं होने के कारण इन परिवारों में रोजगार का संकट है।

मार्क्सवाद की अन्तर्राष्ट्रीयता

रामनिवास बैरवा

कार्ल मार्क्स के समय पूंजीवाद की स्थिति एकाधिकार-मोनोपोली तथा कार्टेलों के निर्माण में अभिव्यक्त होती थी। तब उपनिवेशों के लिए पूंजीवादी देशों में संघर्ष होते थे, लंबे समय तक चलने वाले युद्ध होते थे। आज पूंजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के माध्यम से अपनी साम्राज्यवादी गतिविधियों को पूरा करता है। यह दुनिया का अन्तर्राष्ट्रीयकरण है। इस अन्तर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में मार्क्स के अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा समाज व्यवस्था के संबंध में वे निष्कर्ष हैं जो स्थानीय, राष्ट्रीय विशेषताओं को संरक्षित रखते हुए उन्हें उनके अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप में अभिव्यक्त करते हैं।

कार्ल मार्क्स मानव इतिहास के पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र के परम्परागत विषय -आत्मा-परमात्मा और धर्म से अलग हटकर समाज के ऐतिहासिक एवं भौतिक तथ्यों को केन्द्र बनाकर दर्शन शास्त्र को नया मोड़ दिया है। उन्होंने पहली बार तीन अलग-अलग एकांतिक बनाकर रखी गयी व्यवस्थाओं के अर्न्तसंबधों को स्थापित किया। ऐसा करके उन्होंने मानव-समाज के भूतकाल और वर्तमान की व्याख्या करके मानव-समाज के भविष्य की व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसे अन्तिम रूप में साम्यवाद या "कम्यूनिज्म" नाम दिया है। उस समय और वर्तमान समय में भी देशों और राष्ट्रों की अलग-अलग व्यवस्थाओं को कम्यूनिज्म का प्रस्थान बिंदु नहीं बनाकर अन्तर्राष्ट्रीयता के स्वरूप को प्रतिपादित किया था।

इसका आधार है-"दुनिया के मजदूरों, एक हों।" जब "दुनिया के मजदूरों, एक हों" का नारा दिया गया था तब इस नारे का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ही दिखाई देता है। आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बन चुकी है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में मुद्रा व्यापार और उत्पादनों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। पूंजीवाद की परम्परागत उत्पादन व्यवस्था एकाधिकार और कार्टेल व्यवस्था अब बेमानी हो गई है। छोटे-बड़े सभी ब्रांडों का उत्पादन पहले की तरह एक ही देश में, एक ही जगह पर नहीं किया जा रहा है बल्कि फ्रेंचाइजी और कॉपीराइट के उपयोग के आधार पर किया जा रहा है जो एक ही देश में सीमित नहीं है बल्कि एक से अधिक देशों में उनकी उत्पादन प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इससे कोई भी उत्पादन एक देशीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है।

सामाजिक संरचना में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि कुछेक बड़े पूंजीपतियों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया की पूरी मानव जाति अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए वेतन के लिए काम करते हैं। यह भी एक स्थापित सत्य है कि मानवसमाज का प्रत्येक सदस्य जीवनयापन के लिए सामाजिक सुरक्षा का कवच चाहता है और वह सामाजिक सुरक्षा शिक्षा-चिकित्सा के अलावा जीवन-यापन के लिए नियमित रोजगार और उसके बदले में मिलने वाले वेतन में ही निहित है अत: पूरी दुनिया में सभी वेतन के लिए काम करने वाले, श्रम करने वाले वकर्स ही हैं, श्रमिक ही हैं, मजदूर ही हैं। अत: कार्ल मार्क्स का आह्वान कि "दुनिया के मजदूरों, एक हों" नयी सामाजिकता क ताने-बाने का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप है। देशों की सीमाएं पूंजीवादी शासन व्यवस्था वाले देशों की हैं-मजदूरों-श्रमिकों की शासन व्यवस्था के लिए नहीं है।

1917 में सोवियत क्रान्ति के बाद दुनिया के ऐसे देश जो किसी पूंजीवादी यूरोपीय देश के उपनिवेश नहीं थे, उनमें समाजवादी, कम्यूनिस्ट क्रान्तियों का दौर आया था-लेकिन जो किसी यूरोपीय पूंजीवादी देश के उपनिवेश थे उनमें समाजवादी आंदोलन हो रहे थे लेकिन उपनिवेशवादी देशों के कम्यूनिस्ट-विरोधी, समाजवादी विरोधी कार्रवाइयों, नीतियों के चलते उनमें समाजवादी क्रान्तियां तो सफल नहीं हो सकी, अपितु उनमें सत्ता के लिए संघर्ष निरन्तर चलते रहे। चीन, वियतनाम, कम्यूचिया, कोरिया, तुर्की, यमन, दक्षिण अमरीकी देश समाजवाद के लिए एसे संघर्षों के उदाहरण हैं।

भारत भी मार्क्सवादी समाजवाद के सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है। जब दक्षिणपंथ की बात सामने आती है तो वामपंथ अपने आप ही राजनीतिक और सामाजिक सत्य के रूप में उभर कर सामने आता है। यही कारण है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था दक्षिणपंथ और वामपंथ के बीच हिचकोले ले रही है।

दक्षिणपंथ का उभार वामपंथ की आक्रामकता का कारण है तथा दक्षिणपंथ की पराजय वामपंथ की विजय तो नहीं कही जा सकती लेकिन सामाजिक संरचना के अनुसार राजनीतिक संतुलन का प्रयास है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका आदि दक्षिणपंथ पर वामपंथ को एक अंकुश के रूप में देखा जा सकता है। दक्षिणपंथ की विजय अन्तत: तानाशाही को जन्म देती है और उस तानाशाही पर वामपंथ ही पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है, जैसे हिटलर पर सोवियत संघ की सेनओं ने विजय प्राप्त की थी। अगले सप्ताह रूस में उसी का 80वां विजय दिवस मनाने की तैयारी है जिसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है। वामपंथ, कम्यूनिज्म या समाजवाद कार्ल मार्क्स के निष्कर्षों की राजनीतिक व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ही थे जो अन्तत: मानवजाति की स्वतंत्रता, मानवजाति की मुक्ति का मार्ग बनने का रास्ता दिखता है।

रामनिवास बैरवा
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

राशिफल मंगलवार 6 मई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, मघा नक्षत्र दिन 3:52 तक, धुव्र योग रात्रि 12:30 तक, कौलव करण प्रात: 8:39 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। कुमार योग प्रात: 8:39 से दिन 3:52 तक है। आज बुध मेष राशि में रात्रि 4:07 से प्रवेश करेगा। आज हरि जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:06 से 10:45 तक, लाभ अमृत 10:45 से 2:02 तक, शुभ 3:41 से 5:19 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:49, सूर्यास्त 6:58

मेष
परिवार में शुभ-मांगलिक एवं रचनात्मक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृष
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। भाई-बंधुओं के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय बना रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होगा। परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

तुला
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक एवं रचनात्मक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। शुभ कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।